

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 35/2021

श्रीमती प्रवेशिका पत्नी संदीप जानू जाति जाट निवासी गांव बहादूरवास तहसील व जिला झुंझुनू (राज.)।
—अपीलान्त

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार झुंझुनू (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण आदेश 3892 दिनांक 13.11.2018 तहसीलदार झुंझुनू भूमि खसरा नं.
4337/981 व 981 कस्बा झुंझुनू।

उपस्थित :-

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 23.07.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार (भू-अभिलेख) झुंझुनू के आदेश दिनांक 13.11.2018 नामान्तरकरण संख्या 3892, ख0न0 4337/981 व 981 वाके ग्राम कस्बा झुंझुनू के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्त के अनुसार कस्बा झुंझुनू में भूमि खसरा नं. 980 रकबा 0.360 हैक्टर स्थित है जिसमें से अपीलान्त ने 0.1201 हैक्टर भूमि को खातेदार से कुल बिल ऐवज 4,00,000/- रुपये अदा कर भूमि को दिनांक 26.09.2018 को कय किया और उसी दिन ही विक्रेता ने क्रेता को भूमि का कय भी दे दिया। दिनांक 26.09.2018 को उक्त भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करने के बाद अपीलान्त ने भूमि का विक्रय पत्र की एक प्रति रेस्पोडेन्ट को नामान्तरकरण तस्दीक करने के लिए दे दी और अपीलान्त एक देहात की महिला है जिसको राजस्व कर्मचारियों की औपचारिकता की कोई पता नहीं था व राजस्व रिकार्ड पुनः चैक नहीं किया और नामान्तरकरण दर्ज होना मानकर बैठ गई जबकि दिनांक 01.04.2021 को नकल जमाबन्दी निकालने पर मालूम हुआ कि विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्त के नाम दर्ज नहीं हुआ है। दिनांक 05.04.2021 को अपीलान्त ने जब विवादित विक्रय पत्र का नामान्तरकरण क्र.स. 3892 की प्रति तहसील से प्राप्त की तो नामान्तरकरण खारीज होना पाया गया जो लिखित आधारों के कारण काबिले निरस्त है। माननीय अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आदेश है। अदालत मातहत ने ज्यूडिसीयल माईन्ड अप्लाई नहीं किया है और बिना विधिक प्रावधानों की

राज्य सरकार

24

विवेचना व अध्ययन किये दूर्भावना पूर्ण तरीके से नामान्तरकरण आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने मातहत कर्मचारी भू.अ.नि. की रिपोर्ट का भी अवलोकन नहीं किया और बिना किसी आधार के ही निर्णय जैर बहस पारित किया है। यह कि अदालत मातहत ने कोई भी ऐसा तथ्य दर्ज नहीं किया है जिससे अपने निर्णय के तथ्य को बल मिलता है। और निर्णय के सपोर्ट में कोई भी कानूनी आधार व रिपोर्ट की विवेचना की है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 13.11.2018 खिलाफ कानून है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अदालत मातहत का नामान्तरकरण आदेश स. 3892 दिनांक 13.11.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करे व अपीलान्ट के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि करबा झुंझुनूं में भूमि खसरा नं. 980 रकबा 0.360 हैक्टर स्थित है जिसमें से अपीलान्ट ने 0.1201 हैक्टर भूमि को खातेदार से कुल बिल ऐवज 4,00,000/- रुपये अदा कर भूमि को दिनांक 26.09.2018 को कय किया और उसी दिन ही विक्रेता ने डेता को भूमि का कब्जा भी दे दिया। दिनांक 26.09.2018 को उक्त भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के बाद अपीलान्ट ने भूमि का विक्रय पत्र की एक प्रति रेस्पोजेन्ट को नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के लिए दे दी और अपीलान्ट एक देहात की महिला है जिसको राजस्व कर्मचारियों की औपचारिकता का कोई पता नहीं था व राजस्व रिकार्ड पुनः चैक नहीं किया और नामान्तरकरण दर्ज होना मानकर बैठ गई जबकि दिनांक 01.04.2021 को नकल जमाबन्दी निकालने पर मालूम हुआ कि विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज नहीं हुआ है। माननीय अदालत मातहत का निर्णय स्पीकिंग आदेश नहीं है। अदालत मातहत ने ज्यूडिसीयल माईन्ड अप्लाई नहीं किया है और बिना विधिक प्रमाणों की विवेचना व अध्ययन किये दूर्भावना पूर्ण तरीके से नामान्तरकरण आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने मातहत कर्मचारी भू.अ.नि. की रिपोर्ट का भी अवलोकन नहीं किया और बिना किसी आधार के ही निर्णय जैर बहस पारित किया है। यह कि अदालत मातहत ने कोई भी ऐसा तथ्य दर्ज नहीं किया है जिससे अपने निर्णय के तथ्य को बल मिलता है। और निर्णय के सपोर्ट में कोई भी कानूनी आधार व रिपोर्ट की विवेचना की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अदालत मातहत का नामान्तरकरण आदेश स. 3892 दिनांक 13.11.2018 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करे व अपीलान्ट के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पूर्ण जांच के बाद नामान्तरकरण तस्दीक किया है, जो नियमानुसार तस्दीक किया गया है। जिसमे कोई त्रुटि नहीं है। अपील अपीलान्ट निराधार तथ्यों पर पेश है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 3892 पर दिनांक 13.12.2018 यह तथ्य अंकित करते हुये खारिज कर दिया कि "मौका जांच में उक्त भूमि गैर कृषि उपयोग है अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता है।" उक्त के संबंध में अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत ने भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किये बगैर आदेश पारित किया है। रिकार्ड मातहत के अवलोकन से यह तथ्य साफ है कि नामान्तरकरण में अंकन मुताबिक विक्रय पत्र के भरा गया था तथा भू.अ.नि. ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर भूमि कृषि उपयोग के काम में आने की रिपोर्ट की है। परन्तु अदालत मातहत उक्त भूमि को गैर कृषि उपयोग में माना है जिसके समर्थन में पत्रावली पर कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अदालत मातहत द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायालय की दृष्टि विद्विष्ट नहीं है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 3892 पर पारित आदेश दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौके की जांच करते हुये तथा विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2018 के अनुसार पुनः विधिवत् निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। न्त्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Handwritten signature)

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

23/07/21